साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 05 अप्रैल 2021, वर्ष-7, अंक-01

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

» 15,000 एकड़ वन भूमि पर खुलेंगी कोयले की 22 नई खदानें

» नियम दरकिनार, निजी कंपनियों को पहुंचेगा फायदा

मध्यप्रदेश में दो हजार एकड़ जंगल पर चलेगी कुल्हाड़ी

संवाददाता, भोपाल

देश में एक तरफ सरकार वन क्षेत्रों को बढ़ाने और हरियाली को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कोयले के लिए करीब 15,000 एकड़ जंगल काटने की कवायद चल रही है। इसमें से मप्र में सात खदानों के लिए 838.03 हेक्टेयर (लगभग 2070 एकड़) वन क्षेत्रों पर कुल्हाड़ी चलेगी। इसका खुलासा हाल ही में लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुआ है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने 22 नई कोयला खानें खोलने की योजना बनाई है। इनमें से 7 खदानें मप्र में खुलनी हैं।

गौरतलब है कि मप्र सहित झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जो खनिज संपदा से परिपूर्ण हैं। सरकार इन्हीं चार राज्यों में 22 कोयला खानों के लिए 5966.84 हेक्टेयर (लगभग 14,744 एकड़) वन भूमि को उपयोग में लाया जाएगा। मप्र में सात खानों के लिए 838.03 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल होगा। कोयला खनन के लिए जिन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, वहां सघन वन क्षेत्र है।

मध्यप्रदेश की खदानों से सबसे अधिक कमाई

जून, 2020 में जिन 41 खदानों की नीलामी घोषणा की गई है, उनमें 12 को 2010 में नो-गो के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मप्र में सिंगरौली कोलफील्ड में तीन में से दो ब्लॉकों को नो-गो के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जिन्हें नीलाम किया गया है। मप्र की अधिकांश खदानें नो-गो क्षेत्र में आती हैं। अगर मप्र की खदानों की कमाई का आकलन करें तो कोल खनन की रॉयल्टी में सिंगरौली ने लक्ष्य से अधिक राजस्व अर्जित कर उमरिया, शहडोल समेत एक दर्जन जिलों को पीछे छोड़ दिया है।

बर्बाद हो जाएंगे घने वन क्षेत्र

सरकार की कोयला खदानों को लेकर जो नीति है उससे घने वन क्षेत्र बर्बाद हो जाएंगे। मप्र के शहडोल जिले के इस कोलफील्ड में 110 ब्लॉक हैं, इनमें से 22 ब्लॉक 2010 की सूची के अनुसार नो-गो क्षेत्रों में हैं। जब 2015 में नो-गो सूची का नाम बदलकर अखंडित लिस्ट रखा गया, तो यह संख्या घटकर मात्र एक रह गई। मरवाटोला ब्लॉक को अखंडित क्षेत्र रूप में बरकरार रखा गया था, क्योंकि यह बांधवगढ़ और अचनकमार बाघ अभयारण्यों के बीच स्थित है, जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ने 2014 में चिन्हित किया था। लेकिन सरकार ने अब सोहागपुर कोलफील्ड में अंतिम बचे अखंडित ब्लॉक को भी तोड़ने का फैसला किया है।

सागौन के पेड़ों की बलि

77,482 वर्ग किमी में फैला मप्र का वन क्षेत्र खनिज संपदा से परिपूर्ण है। मप्र में सर्वाधिक पेड़ सागौन के हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर साल के हैं। जिन क्षेत्रों में खदानें खोली जानी है वहां सागौन और साल के वन हैं। अब प्रदेश में खुलने वाली सात कोयला खदानों के कारण सागौन और सान के पेड़ों की बलि दी जाएगी। मप्र से निकलने वाले कोयले से मप्र को कोई लाभ नहीं होता है।

1962 करोड़ का लक्ष्यः चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1962 करोड़ का लक्ष्य दिया गया। इसे 31 मार्च से पहले अर्जित कर सिंगरौली प्रदेश में पहली जगह बनाई है। कोरोनाकाल में भी कोल खनन से माहवार निर्धारित रॉयल्टी को विभाग ने प्राप्त किया है।

इनका कहना है

देश की प्राथमिक ऊर्जा की लगभग 55 प्रतिशत खपत कोयले से पूरी होती है। सरकार की कोशिश है कि देश के कोल भंडार का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। भारत की ऊर्जा जरूरतों का 80 फीसदी कोयला सीआईएल देता है, लेकिन नीतिगत वजहों से 2017-18 से कोयला उत्पादन के लक्ष्य में लगातार कटौती की गई।

प्रहलाद जोशी, कोयला मंत्री

जैव विविधता से भरे इलाकों में कोल-ब्लॉक्स की नीलामी और गो और नो-गो वर्गीकरण की अनदेखी से तीन-तरफा विनाश होगा। इसे रद्द किया करना चाहिए। राजनीतिक रूप से मजबूत बिजली कंपनियों का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री को जलवायु परिवर्तन पर किए वादे को पूरा करना चाहिए।

जयराम रमेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री

2015 के बाद मप्र में कोयला ब्लाकों को वन मंजूरी

वर्ष	कंपनी	कोयला ब्लाक क्षेत्र (हेक्टेयर में)
2015	एसईसीएल	शहडोल 167
2015	एनसीएल	सिंगरौली 424
2017	एसईसीएल	शहडोल 77
2017	डब्ल्यूसीएल	छिंदवाड़ा 54
2017	डब्ल्यूसीएल	छिंदवाड़ा 386
2018	एनसीएल	सिंगरौली 468
2018	डब्ल्यूसीएल	बैतूल 201
2018	डब्ल्यूसीएल	बैतूल 108
2018	टीएचडीएस	सिंगरौली 1283
2018	एनसीएल	सिंगरौली 874
2018	एनसीएल	सिंगरौली 1195
2019	डब्ल्यूसीएल	बैतूल 101
2019	एनसीएल	सिंगरौली 467

■ कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले के भेजे गए नमूने हुए एप्रूव

हरदा का आटा जाएगा दुबई और मलेशिया

विशेष संवाददाता, भोपाल

जहां एक ओर राज्य सरकार खेती को लाभ का धंधा और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर मप्र के गेहूं से बना आटा और मैदा विदेशियों की पहली पसंद बन गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिले का आटा अब दुबई, मलेशिया और अन्य देशों में निर्यात होगा। दरअसल, मध्यप्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात को लेकर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। मध्यप्रदेश के हरदा से पहली गैदा शिपमेंट पर कल्याणी डायनामिक एलएलपी फ्लैग को एपीडा अध्यक्ष की उपस्थिति में किया गया। इसके पूर्व केंद्र की मंशानुरूप निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा एपीडा कार्यालय के लिए मंडी बोर्ड कार्यालय भवन में फरवरी 2021 में स्थान उपलब्ध करा कर कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कमल किशोर आटा मिल हरदा द्वारा मैदा एक्सपोर्ट अनुबंधित का फ्लैग आफ तैयार कर मेसर्स कल्याणी डायनामिक एलएलपी मुंबई स्थित निर्यातक एपीडा से संपर्क कर दुबई में निर्यात के लिए गेहूं का आटा, मैदा सूजी की सोर्सिंग के लिए मदद मांगी। जहां निर्यातक विनय मजुमदार, निदेशक कल्याणी डायनामिक एलएलपी और भोपाल की इकाइयों व एफपीओ के मध्य गत चार मार्च को बैठक कर जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। जिसमें हरदा, विदिशा, इंदौर की विभिन्न आटा मिलों/आटा इकाइयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इनका कहना है

बैठक में एपीडा के कार्य में मंडी बोर्ड द्वारा आवश्यक सहयोग दिए जाने तथा भारत सरकार व मप्र शासन की मंशानुसार मध्यप्रदेश से कृषि उपजों और प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक सहयोग देने की बात कही। कमल किशोर आटा मिल हरदा द्वारा भेजे गए नमूनों को दुबई और मलेशिया देशों ने पसंद पर एप्रूव किया है।

■ **प्रियंका दास**, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड

किसान कल्याण निधि के बाद सरकार की एक और पहल

किसानों को मिलेंगे 'सम्मान कार्ड'

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री कल्याण योजना के माध्यम से चार हजार रुपए प्रतिवर्ष कल्याण निधि देने के बाद अब शिवराज सरकार सम्मान कार्ड देगी। इसके माध्यम से किसान मंडियों में बनाए जाने वाले बाजार से खरीदी कर सकेंगे। यह कार्ड किसानों के सभी बैंक खातों और आधार नंबर से लिंक होंगे। नए वित्तीय वर्ष से कार्ड देने की शुरुआत कर दी जाएगी। वहीं कुछ मंडियों में बाजार भी प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इनमें किसानों को मिलिट्री केंटीन की तर्ज पर रियायती दर पर सामग्री मिलेगी। योजना को लेकर मंडी बोर्ड की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को एक जगह पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार मंडियों में कृषक बाजार बनाने जा रही है। इसके लिए उन मंडियों का चयन किया जा रहा है, जिनके पास पर्याप्त जगह है।

मिलेगी हर विभाग की मददः कृषि विज्ञान मेले में कृषि के सहयोगी उद्यानिकी, मत्स्य-पालन, पशु-पालन, रेशम-पालन, कृषि अभियांत्रिकी आदि विभागों की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कृषि वैज्ञानिक उन्नत कृषि तकनीकी, नरवाई प्रबंधन, ग्रीष्मकालीन मूँग फसल उत्पादन एवं जैविक खेती संबंधी जानकारी किसानों को देंगे। मेले में कृषि और अन्य संबद्ध विभाग स्टॉल लगाकर किसानों को खेती किसानी की जरूरी जानकारी देंगे।

इनका कहना है

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का सरकार का वादा है। उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों को किसान सम्मान-कार्ड दिए जाएंगे। इस कार्ड में कृषि को उन्नत बनाने और कृषि संबंधी योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंचाने की पूरी जानकारी दी जाएगी।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

मध्यप्रदेश के हर जिले में अब होगी कृषि ओपीडी

फसल पर लगे रोगों की जांच और होगा बेहतर इलाज

जबलपुर-हरदा में सफलता के बाद आगे बढ़ी सरकार

संवाददाता, भोपाल

कोई भी फसल हो और उसमें लगने वाले किसी भी तरह की रोगों की जानकारी लेना हो या खेती-किसानी के संबंध में कोई समस्या हो तो मध्य प्रदेश में किसान को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। न ही किसी दुकानदार के पास जाने की जरूरत है। बस उसे अपने जिले की कृषि ओपीडी में जाना होगा, जहां कृषि विशेषज्ञ उसकी हर समस्या का निदान खोजेंगे। प्रदेश के दो जिलों में इसको शुरुआती सफलता मिल चुकी है। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। दरअसल, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए शिवराज सरकार लगातार नवाचार कर रही है। अब सभी जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि ओपीडी खोली जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिसंबर 2020 में जबलपुर में और जनवरी 2021 में हरदा में इसे शुरू किया गया था। इसमें किसानों को दो तरह की सुविधा दी गई हैं। किसान रोग, कीट या अन्य समस्या से प्रभावित फसल के नमूने लेकर केंद्र में आ सकता है। यहां विशेषज्ञ उसका परीक्षण करके निदान बताएंगे। यदि किसान नहीं आ सकते हैं तो वे केंद्र द्वारा जारी वाट्सएप नंबर पर फसल की फोटो भेजकर सलाह ले सकते हैं।

अब विशेषज्ञ सप्ताह में एक दिन जाएंगे गांव

हर जिले में कृषि ओपीडी के साथ एक नवाचार यह भी किया जा रहा है कि अब विशेषज्ञों को सप्ताह में एक दिन गांवों में भेजा जाएगा। वे वहां किसानों को मिट्टी की स्थिति, फसल चक्र, बीज, खाद, और रोग के निदान की सलाह देंगे। विशेषज्ञों को लौटकर गांव के बारे में रिपोर्ट भी देनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर कृषि विभाग रणनीति तय करेगा। यह व्यवस्था नए वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होगी। वहीं जबलपुर केंद्र के विशेषज्ञ एके सिंह ने बताया कि ओपीडी के बाद भी किसानों से लगातार संपर्क रखा जाता है।

इनका कहना है

अभी तक किसान फसलों में रोग लगने पर सीधे दवा दुकानदारों के पास पहुंचता था। दुकानदार उन्हें महंगी दवाएं देते हैं। कई बार सही जानकारी नहीं होने से दवा काम नहीं करती हैं। इससे खेती की लागत बढ़ने के साथ फसल को भी नुकसान होता है। इसे देखते हुए ओपीडी में विशेषज्ञों को नियुक्त कर समस्याओं का समाधान कराया जा रहा है। विशेषज्ञों को भी गांव भेजा जाएगा।

– **कमल पटेल,** कृषि मंत्री, मप्र

जो किसान आते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। मोबाइल नंबर भी लेते हैं ताकि उन्हें बोवनी, दवा के छिड़काव, निदाई और कटाई को लेकर सूचनाएं दी जा सकें। हाल ही में मूंग के संबंध में लगभग 34 हजार किसानों को सलाह दी गई। ऐसी ही सुविधाएं किसानों को हर जिले की कृषि ओपीडी में दी जाएंगी।

एसके तिवारी, फसल वैज्ञानिक, कृषि केंद्र, हरदा

भोपाल में लहसुन की बंपर आवक

- रोज 1200 क्विंटल बिकने आ रही
- थोक भाव 30 रुपए किलो पहुंचे
- थोक-फुटकर में गिरावट का अनुमान

संवाददाता, भोपाल

भोपाल की करोंद मंडी में लहसुन की बंपर आवक हो रही है। प्रतिदिन 1200 क्विंटल तक लहसुन बिकने पहुंच रही है। इस कारण थोक भाव भी घट गए हैं। थोक में लहसुन 30 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। हालांकि, फुटकर मंडी में भाव अधिक है। ग्राहकों को 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक लहसुन मिल रही है। अभी हाल ही में मंडी में 1252 क्विंटल तक लहसुन बिकने आई। इससे न्यूनतम भाव 20 और अधिकतम भाव 30 रुपए प्रति किलो तक रहे। कारोबारियों के अनुसार आसपास के जिलों से लहसुन बिकने आ रहा है। इससे आवक बढ़ गई है। किसान ट्रॉलियों में भरकर लहसुन ला रहे हैं।

10 दिनों में बढ़ गई आवक

करोंद मंडी में मार्च में 299 क्विंटल लहसुन बिकने आई थी। तब भाव 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक थे। इसके बाद आवक बढ़ गई। 18 मार्च को आवक 927 क्विंटल और मार्च अंतिम तक आवक 1200 क्विंटल के पार पहुंच गई। आवक बढ़ने के कारण भाव में भी गिरावट आई, पर आम लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है।

बाजार में अलग-अलग भाव

करोंद स्थित थोक सब्जी मंडी में भले ही लहसुन की बंपर आवक होने से भाव कम हो, लेकिन फुटकर बाजार में भाव दोगुने हैं। हमीदिया रोड स्थित मंडी में लहसुन 30 से 50 रुपए तक बिक रही है। इसके अलावा न्यू मार्केट, एमपी नगर, गर्वमेंट प्रेस क्षेत्र, अवधपुरी, कोलार, होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड, अशोका गार्डन आदि क्षेत्रों में स्थित सब्जी दुकानों में भाव 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं।

इनका कहना है

इन दिनों आलू व प्याज के साथ ही लहसुन भी बंपर मात्रा में बिकने आ रही है। आसपास के जिलों से यहां पर लहसुन लाई जा रही है। इससे भाव में कमी आई है। कुछ दिनों तक आवक इसी तरह बनी रहेगी। इससे भाव कम रहेंगे। आवक बढ़ने के साथ ही थोक व फुटकर भाव में और भी गिरावट होने का अनुमान है।

मोहसिन खान, थोक कारोबारी, आलू, प्याज-लहसुन

जंगल से निकलती रही घास तो संकट में आ जाएंगे वनराज

संवाददाता, भोपाल

बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल बने रहने के लिए प्रयासरत है, पर इसमें कई अड़चनें भी हैं। प्रदेश के जंगलों से हर साल 1053 लाख टन चारा (घास) निकाला जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। यह स्थिति आने वाले समय में जंगल के राजा यानी बाघों के जीवन के लिए संकट पैदा करेगी। सबसे ज्यादा चारा निकाले जाने की जानकारी भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की रिपोर्ट से मिली है। हालांकि यह रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, सिर्फ परीक्षण के लिए अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश भी आई है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में देश में सबसे ज्यादा 526 बाघ हैं। एफएसआई ने ईंधन के लिए ग्रामीणों की जंगल पर निर्भरता को लेकर अध्ययन किया है। इससे पहले यह अध्ययन वर्ष 2011 में हुआ था।

लोगों का चल रहा धंधा

रिपोर्ट के मुताबिक जंगल के पांच किमी की परिधि में बसे गांवों के लोग जलाऊ और छोटी इमारती लकड़ी के साथ चारा भी

निकालते हैं, जो पशुओं के खाने और बेचने के काम आता है। प्रदेश के जंगलों से हर साल 1053 लाख टन चारा निकल रहा है।

संख्या होगी प्रभावित

देश में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे पर गुजरात है। यह स्थिति मप्र में बढ़ते बाघों के लिए ठीक नहीं है। बाघों का जीवन चक्र शाकाहारी वन्यप्राणियों पर निर्भर है। शाकाहारी जीव घास के मैदानों पर। वे घास में ही छिपते और प्रजनन करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि घास के मैदान ही नहीं रहेंगे, तो शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या पर असर पड़ना स्वाभाविक है।

घांस के फायदे

चीतल, सांभर, हिरण, काले हिरण, नीलगाय सहित अन्य शाकाहारी वन्यप्राणियों को पेट भरने, छिपने और प्रजनन में घास के मैदान मददगार होते हैं और शाकाहारी वन्यप्राणी बढ़ेंगे, तो बाघों को जंगल में खाना मिलेगा। फिर वे बाहर नहीं निकलेंगे और वे दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे या शिकारियों के जाल में नहीं फंसेंगे।

ज्यादा मौतें भी प्रदेश में ही

देश में बाघों की सबसे ज्यादा मौतें भी मध्य प्रदेश में ही होती है। पिछले साल यहां 28 बाघ मरे थे। इनमें से ज्यादातर की मौत संरक्षित क्षेत्र के बाहरी इलाके में हुई है। इनमें शिकार और दुर्घटना के मामले भी शामिल हैं।

इनका कहना है

बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए घास के मैदान तैयार करने पड़ते हैं। प्रदेश के कई पार्कों में ऐसा किया गया है। जिन संरक्षित क्षेत्रों (टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और अभयारण्य) से वनग्राम विस्थापित किए गए हैं, वहां घास के मैदान तैयार किए गए हैं। इसका असर वर्ष 2018 की बाघ गणना में दिखाई दिया है।

डॉ. सुदेश वाघमारे, पूर्व उप संचालक, वन विहार नेशनल पार्क, भोपाल

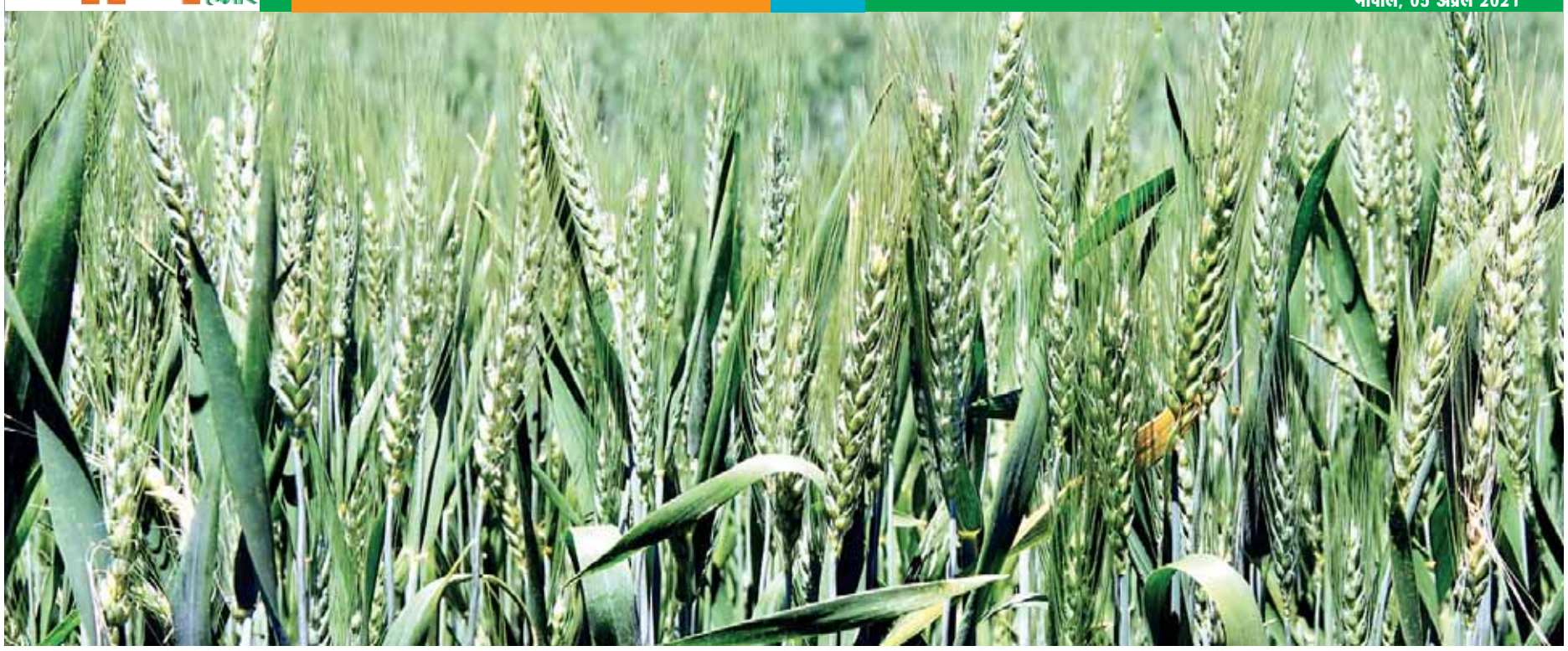

केंद की रिपोर्ट | **मप्र में 41 वर्ग किमी कृषि भूमि बढ़ी**

» देश में चार साल में 49,051 वर्ग किमी कृषि भूमि घटी

मप्र बना देश में नजीर, रकबा बढ़ने के साथ उत्पादन में भी बढ़ोतरी

उपलब्धिः मप्र में कृषि भूमि के साथ ही उत्पादन बढ़ा

हैरत की बातः मात्र 2 स्क्वायर किमी क्षेत्र चरनोई

विशेष संवाददाता, भोपाल

भारत में कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। आज भी देश की 60 फीसदी ग्रामीण आबादी अपनी जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। जबकि यदि किसानों की बात करें तो देश के 82 फीसदी किसान छोटे और सीमांत हैं। ऐसे में फसल उनके लिए कितनी मायने रखती है वो बताने की जरुरत नहीं है। लेकिन विसंगति यह है कि मप्र को छोड़कर देशभर में कृषि भूमि लगातार घट रही है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में 4 वर्ष में 49,051 वर्ग किमी कृषि भूमि घटी है। वहीं इस दौरान मप्र में 41 वर्ग किमी कृषि भूमि बढ़ी है। देश में कृषि भूमि में 49,051 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2015-16 के बाद और तेजी से कृषि भूमि घटी है। लेकिन मप्र के लिए सुखद संकेत यह है कि यहां खेती का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। मप्र सरकार की नीतियों के कारण खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश अनाज के अधिक उत्पादन और उपार्जन में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस कारण प्रदेश को पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है।

इनका कहना है

पिछले 15 साल के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार ने खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित किया है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में खेती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। प्रदेश में खेती लाभ का धंधा बनती जा रही है। प्रदेश सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाकर लोग खेती के प्रति आकर्षित हो रहे हैं।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

सुखदः प्रदेश में खेती-किसानी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा

मध्यप्रदेश में 1,88,139 वर्ग किमी कृषि भूमि

क्षेत्रफल के मामले में मध्यप्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्यप्रदेश में कुल 238252 वर्ग किमी भू-भाग है। 2011-12 में प्रदेश में 1,88,098 वर्ग किमी में खेती की जाती थी। जो अब बढ़कर 1,88,139 वर्ग किमी हो गई है। यह इस बात का संकेत है कि प्रदेश में खेती-किसानी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। वर्तमान में प्रदेश में कुल परती भूमि 24,854 वर्ग किमी है। जबकि 5,722 किमी में रहवासी क्षेत्र हैं, जहां आवास, दफ्तर, उद्योग या अन्य निमार्ण हुए हैं। वहीं 80,617 स्क्वायर किमी में वन क्षेत्र है। वहीं गीली और पानी वाली भूमि 8,919 स्क्वायर किमी है। हैरानी की बात यह है कि प्रदेश में मात्र 2 स्क्वायर किमी क्षेत्र चरनोई है। प्रदेश में चरनाई भूमि का बड़े स्तर पर अतिक्रमण हुआ है और लोग उसे खेत में बदलकर कृषि कार्य कर रहे हैं।

अन्य राज्यों के लिए नजीर बना मप्र

देश में जहां एक तरफ कृषि भूमि घट रही है, वहीं मप्र में साल दर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है। वह भी तब जब मप्र में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मप्र देश के अन्य राज्यों के लिए नजीर बन सकता है। साथ ही देश के लिए जरुरी हो जाता है कि सरकार देश में कृषि भूमि को संरक्षण प्रदान करे साथ ही उसका पूरी तरह से उपयोग किया जाए यह भी सुनिश्चित करे।

जलस्रोतों के क्षेत्रफल में कमी

जहां 2011-12 में 7,25,543 वर्ग किमी क्षेत्र पर जंगल थे वो 2015-16 तक 7,914 वर्ग किमी घटकर 7,17,629 वर्ग किमी में ही सिमट गए थे। जबकि इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 24.56 फीसदी भू-भाग पर जंगल थे। घास और चराई स्थल की बात करें तो उसमें भी कमी आई है। इसका विस्तार 25,397 से घटकर 23,551 किमी का रह गया है।

मप्र में जैविक खेती और जैविक खाद को बढ़ावा

मप्र में भी भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। ऐसे में सरकार जैविक खेती और जैविक खाद को बढ़ावा दे रही है। यही नहीं प्रदेश में कृषि भूमि का बढ़ाने के लिए चंबल के बीहड़ को खेती के लिए तैयारी करने की तैयारी चल रही है। चंबल के बीहड़ों के समतलीकरण और कृषि योग्य बनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय और मप्र सरकार के बीच पिछले दिनों मीटिंग हुई। जुलाई में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व बैंक के प्रतिनिधि और मप्र के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक में चंबल संभाग की तीन लाख हेक्टेयर परती बीहड़ भूमि के प्लान के लिए समझदारी विकसित हुई है।

मप्र में भूमि	(स्क्वायर किमी)
कृषि भूमि	183563
परती	4173
पौधरोपण	402
बंजर पहाड़ी	380
रेवीनस लैंड	1491
रद्दी भूमि	22983
माइनिंग	474
रूलर	3190
अर्बन	2057
वन भूमि	80617
चरनोई	02
नदी क्षेत्र	3205
जल निकाय भूमि	5714

प्रदेश में कृषि भूमि बढ़ी

मप्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य सहारा कृषि है और यही एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जो राज्य की ग्रामीण आबादी को बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया कराने के साथ जीविका उपार्जन का विकल्प देता है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक मप्र में जीविकोपार्जन के लिए कुल कामकाजी लोगों के 69.8 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में कुल कामकाजी लोगों के 85.6 फीसदी कृषि पर आश्रित थे। इसमें 31.2 फीसदी किसान और 38.6 फीसदी खेतीहर मजदूर थे। लेकिन विसंगति यह देखिए की एक तरफ जहां प्रदेश में कृषि भूमि बढ़ी है, वहीं किसानों के खेतीहर मजदूर बनने के आंकड़े भी बढ़ हैं।

70 लाख किसान खेतीहर मजदूर

सांख्यकीय विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2001 में प्रदेश में 1 करोड़ दस लाख किसान थे जो 2011 में घटकर 98 लाख हो गए। आज की स्थिति में 70 लाख हो गए हैं। वहीं खेतीहर मजदूरों की संख्या 74 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गई है। कृषि योग्य जमीन बढ़ी है लेकिन उसके हिस्से बहुत हो गए हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि किसान या तो खेतीहर मजदूर बन

रहे हैं या फिर गांव से पलायन कर शहरों में मजदूरी का काम कर रहे हैं। प्रदेश में प्रति किसान भूमि का औसत 2 हेक्टेयर था जो अब घटकर 1.29 हेक्टेयर हो गया है। एक किसान के पास अपना परिवार के पालन पोषण के लिए ढाई से तीन एकड़ जमीन होती है जिसका उत्पादन एक परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए तेजी से पलायन भी हो रहा है। जिसे समय रहते रोकना सरकार के लिए चुनौती बन गया है।

65 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य

मप्र कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की सारी अर्थव्यवस्था कृषि से ही चलती है। प्रदेश की 70 फीसदी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 56 फीसदी जमीन पर खेती होती है। वर्तमान में प्रदेश 40 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। सरकार ने इसको बढ़ाकर अगले चार साल में 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई करने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि हर रोज लगभग 2500 किसान खेती छोड़ रहे हैं। देश के किसान परिवारों की औसत आय 20 हजार रुपए वार्षिक है। कृषि को अपना मुख्य पेशा बताने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है।

'डार्क जोन' में देश के 264 जिले

दुनिया में कुल कृषि योग्य भूमि मात्र 11 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह 56 प्रतिशत है। दुनिया में पाई जाने वाले 64 में से 46 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। इसी तरह, वर्षा, सतही और भूमिगत जल के हिसाब से भी भारत काफी संपन्न है। देश में हर साल करीब 4,000 अरब घन मीटर वर्षा होती है। हालांकि हम इसका मात्र 10-15 ही उपयोग कर पाते हैं, बाकी बेकार बह जाता है। देश के कुल भू-भाग का 30 करोड़ हेक्टेयर जलाच्छादित है। देश में करीब 445 नदियां हैं, जिनकी कुल लंबाई दो लाख किमी है। एक अनुमान के अनुसार, 1947 में देश में वर्षा जल संरक्षण के लिए 28 लाख झील और पोखर थे, पर आज उनकी संख्या में कमी आई है। हरित क्रांति के कारण भूमिगत जल का दोहन हुआ, जिससे देश के 264 जिले 'डार्क जोन' में आ गए हैं।

गांव की निर्धन महिलाओं को सशक्त बनाना लक्ष्य

महेंद्र सिंह सिसोदिया
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 से ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिये स्व-सहायता समूह बनाकर उनके संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिशन द्वारा प्रदेश में अब-तक समस्त जिलों के 44 हजार ग्रामों में 3 लाख 22 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा वर्ष 2012 से ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिये स्व-सहायता समूह बनाकर उनके संस्थागत विकास तथा आजीविका के संवहनीय अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मिशन द्वारा प्रदेश में अब-तक समस्त जिलों के 44 हजार ग्रामों में 3 लाख 22 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों से लगभग 36 लाख 53 हजार महिलाओं को जोड़ा जा चुका है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित करके सहयोगात्मक मार्गदर्शन करना तथा समूह सदस्यों के परिवारों को रुचि अनुसार उपयोग स्व-रोजगार एवं कौशल आधारित आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि मजबूत बुनियादी संस्थाओं के माध्यम से निर्धन परिवारों की आजीविका को संवहनीय एवं स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके। स्व-सहायता समूहों से जुड़ चुके अधिकांश परिवार आज सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर रहे हैं। उनके द्वारा न सिर्फ आर्थिक बदलाव लाया जा रहा है, बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। प्रदेश में आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व-सहायता समूहों से जुड़े परिवारों में से 12 लाख 60 हजार से अधिक परिवार कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़े हैं जबकि लगभग 4 लाख 11 हजार से अधिक परिवार गैर कृषि आधारित लघु उद्यम आजीविका गतिविधियों से जुड़कर काम कर रहे हैं। समूहों को मिशन द्वारा चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि आपदा कोष तथा बैंक लिंकेज के रूप में वित्तीय सहयोग किया जा रहा है। इस राशि से उनकी छोटी बड़ी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जिससे वह साहूकारों के कर्जजाल से बच जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिए इस वर्ष 1400 करोड़ रुपए से अधिक बैंक ऋण समूहों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा तय किया गया है। इनमें से 18 मार्च 2021 तक 1325 करोड़ से अधिक समूहों को वितरित किए जा चुके हैं। इस राशि से ग्रामीण तबके के परिवारों की आजीविका गतिविधियों को शुरू करने तथा सुदृढ़ करने के अवसर कई गुना बढ़ गए हैं।

यह राशि जैसे-जैसे समूहों में पहुंचती जा रही है, निर्धन परिवारों के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति में तेजी से सुधार दिखाई दे रहा है जिससे ऋण वापसी और भी सरल हो गई है। सरकार द्वारा किए जा रहे इस सहयोग से ग्रामीण निर्धनों का कर्ज बोझ कम हुआ है। साथ ही बचत के अवसर भी बढ़े हैं। सरकार द्वारा समूहों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को अब 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार की प्राथमिकता एवं आजीविका मिशन के प्रयासों का ही परिणाम है कि जो समूह सदस्य महिलाएं कुछ वर्षों पहले मुश्किल से तीन-चार हजार रुपए प्रतिमाह आय अर्जित कर पाती थीं, आज ऐसी लाखों महिलाएं जो सम्मानपूर्वक प्रतिमाह 10 हजार रुपए से अधिक आय संवहनीय रूप से अर्जित करने लगी हैं। समूहों में जुड़कर न सिर्फ उन्होंने अपनी आय के संसाधनों में वृद्धि की है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी उनकी रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों के अलावा शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए परिवार का सहारा बन रही हैं। मप्र के आजीविका उत्पादों को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर वृहद बाजारों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उचित दाम में सामान सीधा खरीदा एवं बेचा जा सके, जिसका फायदा समूह सदस्यों को अधिक से अधिक मिल सके। समूहों और ग्राहकों के बीच कोई बिचौलिया न हो, इसके लिए आजीविका गतिविधि से बनाई जा रही वस्तुओं को बेचने के लिए, बाजार उपलब्ध कराने के लिए मप्र आजीविका मार्ट पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर समूहों के उत्पाद दर्ज किए जा रहे हैं। पोर्टल के माध्यम से ही ग्राहक सीधे संपर्क कर वस्तुऐ खरीद सकेंगे।

प्रदेश में शासकीय स्कूलों के छात्रों की गणवेश सिलाई का काम समूहों को दिया गया है। पिछली बार समूह सदस्यों ने अच्छा काम किया था। इस बार फिर से समूहों को स्कूल गणवेश का काम दिया गया है। काम में पारदर्शित बनाये रखने तथा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए स्व-सहायता पोर्टल बनाया गया है, जिसकी सहायता से यह काम और भी आसान हो जाएगा। मिशन द्वारा दिए जा रहे लगातार प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय सहयोग एवं सहयोगात्मक मार्गदर्शन से लाखों परिवारों की निर्धनता दूर हो गई है। प्रशिक्षणों का ही परिणाम है कि समूह सदस्यों के अन्दर गरीबी से उबरने की दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप वह आगे बढ़कर पात्रता अनुसार अपने हक, अधिकार न केवल समझने लगे हैं बल्कि प्राप्त करने लगे हैं। मिशन के प्रयासों से ग्रामीण निर्धन परिवारों के जीवन में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों में महिलाओं की आय मूलक गतिविधियां करने के अवसर नहीं मिलते थे, उनका जीवन केवल चूल्हे-चौके व घर की चार दिवारी तक की सीमित रह जाता था। घर के संचालन, आय-व्यय, क्रय-विक्रय आदि सहित अन्य मुद्दों पर निर्णय में पुरुषों का एकाधिकार था, यहां तक कि महिलाओं के आने-जाने, उठने-बैठने, पहनने-ओढ़ने, खाने-पीने आदि जैसे व्यक्तिगत मुद्दों पर भी उनकी राय लेना मुनासिब नहीं समझा जाता था, बल्कि सब कुछ एकतरफा उन पर थोप दिया जाता था। कभी परंपरा तो कभी संस्कार मर्यादा के नाम पर महिलाओं के पास इन्हें ढोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। उनकी अपनी कोई पहचान इच्छा-अनिच्छा, सहमति-असहमति नहीं होती थी। घर के संचालन एवं खेती बाड़ी तथा व्यवसायिक कार्यों में महिलाओं की राय लेना तो जैसे सपनों की बातें हों। समूहों, ग्राम संगठनों, संकुल स्तरीय संघों की नियमित बैठकों में भागीदारी करने से उनकी समझ व सक्रियता बढ़ गई है। साथ ही उनकी कार्यशैली में निखार एवं आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी हुई है।

स्वच्छता के साथ पर्यावरण सुरक्षा के प्रति भी जागरूक मध्यप्रदेश

हरदीप सिंह डंग
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में स्वच्छता के नए आयाम स्थापित करने के साथ ही जल-वायु की शुद्धता, संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास निरंतर जारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के कचरे एवं मल-जल से होने वाले प्रदूषण से मुक्त करने के लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। युवाओं को पर्यावरण संबंधी विषयों में प्रशिक्षित करने के लिये एप्को द्वारा डिप्लोमा कोर्स चलाने के साथ छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए जाते हैं। पर्यावरण जागरूकता के साथ ही इनसे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के दौरान जनित 2200 मीट्रिक टन कोविड वेस्ट और 6120 मीट्रिक टन जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट का निष्पादन प्रदेश में स्थापित इन्सिनरेटर्स में करवाया। इससे कचरा इधर-उधर नहीं फैला और कुछ हद तक संक्रमण फैलने पर अंकुश लग सका। प्रदेश के तालाबों और जल-संरचनाओं के संरक्षण का काम भी जारी है। रतलाम के अमृत सागर तालाब के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति के बाद 21 करोड़ रुपए से संरक्षण का कार्य आरंभ कर दिया गया है। वहीं सीता सागर, दतिया के संरक्षण एवं प्रबंध की योजना केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृत हो गई है। जल्द ही 13 करोड़ 85 लाख की लागत की इस परियोजना का कार्य शुरू होने जा रहा है। धार जिले के मुंज सागर, देवी सागर और धूप सागर तालाब के लिए 37 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा गया है। योजना में प्रदेश के अन्य जिलों के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के पालन में मंदसौर जिले की शिवना नदी को प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए लगभग 100 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। अति प्रदूषणकारी प्रकृति के 211 उद्योगों में सतत ऑनलाइन मॉनीटरिंग उपकरणों की स्थापना कराई गई। इसकी निगरानी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में स्थापित इन्वायरमेंट सर्विलेंस सेंटर, भोपाल द्वारा की जा रही है। प्लास्टिक पैकिंग उपयोग करने वाली इकाइयों के लिये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसबिलिटी (ईपीआर) के तहत 16 ईपीआर संस्थाओं का पंजीयन किया गया है। इससे प्लास्टिक पैकिंग करने वाली इकाई अपने वेस्ट का निष्पादन पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से कर रही हैं और प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा। नर्मदा नदी में प्रदूषण पर निगरानी रखने के लिए उद्गम स्थल अमरकंटक से अलीराजपुर तक 50 स्थलों पर जल गुणवत्ता मापन का कार्य किया जा रहा है। नर्मदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थापित जल प्रदूषणकारी उद्योगों में आवश्यक दूषित जल उपचार संयंत्रों की स्थापना से निस्त्राव की स्थिति शून्य हो गई है। अन्य नदियों की जल शुद्धता जांचने के लिए भी निरंतर जल गुणवत्ता मापन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के नगरों का चहुंमुखी हो रहा विकास

भूपेंद्र सिंह
मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास, मप्र

किसी प्रदेश के शहर की समृद्धि और विकास की झलक ही उस प्रदेश के बारे में लोगों का माइंड सेट बनाती है। यह अतिश्योक्ति नहीं है कि मध्यप्रदेश देशवासियों ही नहीं, विदेशियों का भी यह माइंड सेट बनाने में सफल हुआ है, कि प्रदेश चहुंमुखी विकास कर रहा है। जापान का एक प्रतिनिधि इंदौर में एक सम्मेलन में शामिल होने आता है और वह सुबह इंदौर शहर का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि कचरा ढूंढने के लिए करता है। जब इस बारे में पूछा जाता है, तो वह कहते हैं कि लगातार 4 वर्ष से देश में स्वच्छता में नम्बर-एक पर रहने वाले शहर की स्थिति देखने गया था। मैं संतुष्ट हूं। इस तरह प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरों का लगातार विकास हो रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में प्रदेश विगत वर्ष से एक पायदान ऊपर अब तीसरे स्थान पर है। भोपाल को देश की स्वच्छतम स्व-संवहनीय राजधानी का गौरव प्राप्त हुआ। शहरी विकास की भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में पहली बार प्रदेश के चार शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में शीर्ष 20 में सम्मिलित हैं। सिर्फ स्वच्छ सर्वेक्षण में ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस योजना में मप्र में विभिन्न घटकों में कुल सात लाख 99 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक कुल 2 लाख 87 हजार आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश ने ही पूरे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री के माध्यम से एक लाख हितग्रहियों को गृह प्रवेश कराया गया। आवास उपलब्ध कराने के लिए आवासीय भूमि का पट्टा भी भूमिहीन शहरी परिवारों को उपलब्ध कराया गया है। मलिन बस्ती के शहरी गरीबों को दी जाने वाली अनुदान राशि के बराबर ही गैर मलिन बस्ती के शहरी गरीबों को भी राज्य सरकार ने डेढ़ लाख का अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश स्मार्ट सिटी मिशनमें देश के 4 अग्रणी राज्यों में है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भोपाल स्मार्ट सिटी देश में प्रथम तथा इंदौर स्मार्ट सिटी चतुर्थ स्थान पर है। भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार का दृढ़ निश्चय है कि सभी शहरों में नल से पानी दिया जाए। इसे मूर्तरूप देने के लिये 378 नगरीय निकाय की जल आवर्धन योजना को पूर्ण करने के लिए वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नवगठित 29 नगरीय निकायों तथा नगरों के विस्तार/सीमावृद्धि के कारण पहले स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त कार्यों के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल परियोजना के दूसरे चरण की स्वीकृति दी जा रही है। सीवरेज की स्वीकृत 5354 करोड़ की 52 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं। शेष दिसंबर 2022 तक पूरी करने का लक्ष्य है। ई-नगरपालिका सॉफ्टवेयर तैयार कर सभी नगरीय निकायों में लागू किया गया है। सभी म्यूनिसिपल सेवाएं ऑनलाईन की गयी हैं। शहरों में ऑनलाईन भवन अनुज्ञा देने के लिये आटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को लागू किया गया है। नगरीय निकायों की राजस्व आय में वृद्धि किए जाने के उददेश्य से भारत सरकार के निर्देश के क्रम में संपत्ति कर के अधिरोपण को कलेक्टर गाइड-लाइन से जोड़ा गया है। पेयजल, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार के अधिरोपण को युक्तियुक्त कर इन सेवाओं के प्रदान पर होने वाले व्यय की शतप्रतिशत वसूली सुनिश्चित की गई है। इन सुधारों के फलस्वरूप भारत सरकार ने प्रदेश की जीडीपी का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लिए जाने की स्वीकृति दी गई है। नगरीय निकायों की अचल संपत्तियों के अंतरण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्तमान प्रावधानों में संशोधन की तैयारी है। अब राज्य सरकार ने अग्निशमन तथा लिफ्ट से संबंधित प्रावधानों को म.प्र.भूमि विकास नियम-2012 में सम्मिलित किया है।

टमाटर के भाव ने किसानों के निकाले आंसू, सड़कें लाल

» बाजार नहीं मिलने से किसानों ने सड़क पर फेंक दिए टमाटर

» रायसेन टमाटर जिला घोषित और जानवर खा रहे सब्जियां

संवाददाता, रायसेन

आम लोगों की जेब ढीली करने वाला टमाटर अब किसानों के आंसू निकाल रहा है। दरअसल, रायसेन का टमाटर किसान इस साल बर्बाद हो गया। बंफर फसल हुई तो उम्मीद थी कि अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन बाजार नहीं मिलने के कारण इस बार लागत भी नहीं निकल पायी। जेब में पैसा नहीं तो माल की ढुलाई भी कैसे करें इसलिए किसानों ने मवेशियों के खाने के लिए टमाटर सड़क और नालियों में फेंक दिए हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत रायसेन को टमाटर जिला घोषित किया गया है। यहां का टमाटर उत्तर और दक्षिण भारत जाता था। लेकिन कोरोना काल और ऊपर से दक्षिण में इस बार टमाटर की भरपूर पैदावार ने रायसेन के टमाटर का बाजार पूरी तरह से चौपट कर दिया। टमाटर के सही दाम नहीं मिलने पर किसान टमाटर फेंकने के लिए मजबूर हैं। हालात ये हैं कि इस बार लागत, बीज, दवाइयां और अन्य खर्च तक नहीं निकल पाया। रायसेन में टमाटर से सड़कें और नहरें लाल हो रही हैं।

स्थानीय बाजार में उपज का दाम नहीं मिल पा रहा। यहां के बाड़ी इलाके में टमाटर की पैदावार होती है। इस बार बंपर क्रॉप के कारण भाव औंधे मुंह गिर पड़े हैं। टमाटर खेतों में सड़कर खराब होने लगा है। दर्जनों बीघा जमीन पर टमाटर की पैदावार करने वाले किसानों को इस बार बीज, दवाई और अन्य खर्च तक निकालना मुश्किल हो गया है। 22 किलोग्राम के एक क्रेट के अब 40 रुपए मिल रहे हैं। इसके बावजूद खरीददार नहीं मिल रहे हैं।

रायसेन से नहीं निकल पाया टमाटर

रायसेन से काफी ज्यादा मात्रा में टमाटर उत्तर और दक्षिण भारत जाता था। इसलिए यहां बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। इस बार बारिश ज्यादा होने के कारण बाजार में महंगा गेहूं पहुंचा तो दोनों जगह टमाटर की डिमांड कम हो गयी। इसलिए रायसेन का टमाटर रायसेन में ही रह गया।

उम्मीदों पर फिरा पानी

उत्तर दक्षिण भारत के व्यापारी आने से यहां के किसानों को अच्छा रेट मिलने लगा था। लोगों ने एक दूसरे की खेती देख कर टमाटर की खेती चालू कर दी। यहां तक की किराए पर जमीन लेकर टमाटर लगाया, लेकिन इस बार सारा प्लान चौपट हो गया। अब उद्यानकी विभाग नई तकनीकी के साथ खेती कराने और शासकीय योजनाओं का फायदा किसानों को पहुंचाने के लिए सोच रहा है।

इनका कहना है

मैं पिछले 14 साल से टमाटर की खेती कर रहा हूं। इस साल 15 एकड़ में टमाटर की खेती की है। चार लाख की किराए से जमीन ली, लेकिन अब लागत भी नहीं निकल पायी। हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए।

अकरम, किसान, टमाटर उत्पादक

मैं 12 साल टमाटर की खेती कर रहा हूं। चार एकड़ में टमाटर लगाए हैं। लगभग डेढ़ लाख रुपए खर्च आया। लेकिन अब एक क्रेट 40 से 50 रुपए में बिक रही है। लॉकडाउन के कारण माल उठाने के लिए गाड़ी नही मिल रही हैं।

सुरेंद्र कुमार तिवारी, किसान, टमाटर उत्पादक

पेड़ के रूप में अपनों को जिंदा रखने की खुशी

जबलपुर में मृतकों की याद को पेड़-पौधों के रूप में संजोया जा रहा

मुहिम से जुड़कर अब तक जबलपुर में 100 पौधे रोपित किए जा चुके

संवाददाता, जबलपुर

न कब्र न मुक्तिधाम! क्योंकि वो मृत्यु के बाद भी जिंदा हैं। लोगों को सुनने-पढ़ने में आश्चर्य जरूर होगा कि आखिर मौत के बाद भी कोई कैसे जिंदा रह सकता है। इस सवाल का जवाब संस्कारधानी जबलपुर की एक सामाजिक संस्था कदम ने खोज निकाला है। ये संस्था मृतक की राख में नए पौध लगवाकर उसकी यादों और अंश को जीवित रख रही है। संस्था की मुहिम से अब तक सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं। वो अपनों को खोने के बाद भी उन्हें पेड़ के रूप में जिंदा रखे हुए हैं। यह बात तो साबित हो चुकी है कि पेड़-पौधों में भी इंसानों की तरह ही जान होती है। वह भी सांस लेते हैं वह भी धीरे-धीरे बढ़ते हैं, तो फिर इंसान और पौधों में क्या अंतर। इसी विज्ञान को साथ लेकर संस्था ने अंश रोपण अभियान की शुरुआत 10 साल पहले की थी। उनकी इस मुहिम से जुड़कर अब तक जबलपुर में 100 से ज्यादा ऐसे पौधे रोपित किए जा चुके हैं।

बेटा आज भी उनके बीच...

कुछ ऐसी ही कहानी यहां रहने वाले लोधी परिवार की भी है। 4 साल पहले उनका नौजवान बेटा बीमारी के कारण चल बसा। अपने बेटे के जाने के गम में पूरा परिवार सदमे में था। फिर उन्हें संस्था से जानकारी मिली कि अंश रोपण के जरिए वह अपने बेटे को अपने बीच बनाए रख सकते हैं। लोधी परिवार ने अपने बेटे की राख का इस्तेमाल कर बेल का पौधा लगाया। आज वो पेड़ बन चुका है और पूरा परिवार उसे अपने बेटे की तरह दुलार करता है।

पेड़ के रूप में सिर पर पिता का साया

जबलपुर के रामचरण कनोजिया की मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है। रामचरण के पुत्र अनिल बताते हैं कि उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां और उनके पूरे परिवार का सहारा छिन गया था। तभी उन्हें जानकारी लगी की अंश रोपण के जरिए वह अपने पिता को अपनों के बीच हमेशा बनाए रख सकते हैं, तो उन्होंने अंतिम संस्कार के बाद अपने पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के बाद कुछ राख अपने पास रख ली और उसका इस्तेमाल कर अपने घर में इलायची का एक पौधा लगा लिया। 3 साल में आज वह पौधा एक पेड़ का रूप ले रहा है। रोजाना पूरा परिवार इस पौधे की सेवा करता है। त्योहारों में पौधे के पास समय व्यतीत किया करता है। इससे उन्हें महसूस होता है कि उनके पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ है।

ओला प्रभावित गेहूं भी खरीदेगी सरकार!

» बे-मौसम बारिश और ओलावृष्टि से चमक विहीन हो गया गेहूं

» शिवराज सरकार ने समर्थन पर खरीदने केंद्र से मांगी अनुमति

विशेष संवाददाता, भोपाल

इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा सहित मध्य प्रदेश के 24 जिलों में गेहूं की फसल बारिश और ओलावृष्टि से चमकविहीन हो गई है। समर्थन मूल्य पर यदि राज्य सरकार इसे खरीद भी लेती है तो भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सेंट्रल पूल में तब तक इसका उठाव नहीं करेगा, जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे देती है। प्रदेश के बड़े हिस्से में गेहूं प्रभावित होने की स्थिति को देख शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार से चमकविहीन गेहूं खरीद की अनुमति मांगी है।

वहीं उधर, कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है केंद्र सरकार भी किसानों के प्रति संवेदनशील है और चमकविहीन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति जल्द मिल जाएगी। पिछले साल भी प्रदेश को इस तरह की विशेष अनुमति दी गई थी, जिसके बाद एफसीआई सेंट्रल पूल में गेहूं लेने के लिए राजी हुआ था। प्रदेश में पिछले साल अच्छी बारिश हुई और गेहूं का रकबा 98 लाख हेक्टेयर हो गया। अनुकूल मौसम के चलते बंपर पैदावार होने का अनुमान कृषि विभाग ने लगाया। इसी आधार पर खाद्य विभाग ने समर्थन मूल्य पर 135 लाख टन खरीदी की तैयारी शुरू की। इसी दौरान जब फसल खेतों में पककर खड़ी थी, तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे फसल को काफी नुकसान पहुंचा। सरकार ने क्षति का आकलन कराने के लिए राजस्व और कृषि विभाग के अमले से सर्वे कराया है। इसके आधार पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रविधानों के तहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, पर जो गेहूं बच गया है, उसे समर्थन मूल्य पर खरीदने में समस्या आने की संभावना है।

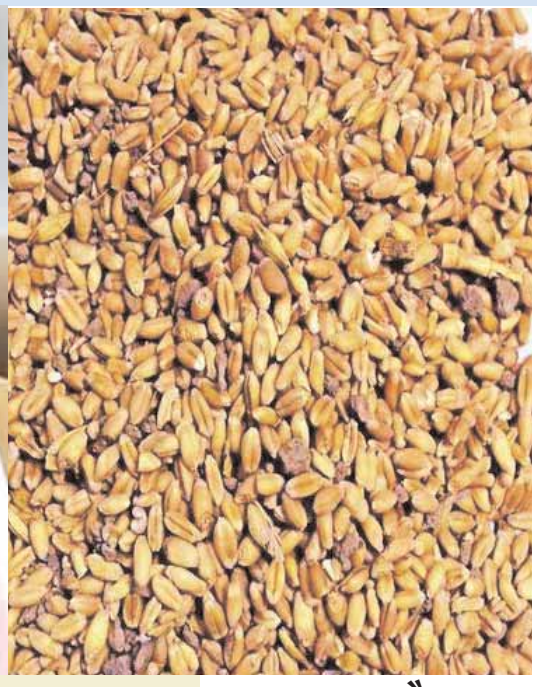

केंद्र को भेजा प्रस्ताव

पानी लगने की वजह से गेहूं की चमक प्रभावित हो गई है। एफसीआई के प्रविधानों के अनुसार चमक विहीन गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा सकता। राज्य खरीद भी लेता है तो एफसीआई इसे सेंट्रल पूल में तब तक नहीं लेगा, जब तक केंद्र सरकार विशेष अनुमति नहीं देती है। इसको लेकर राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने खाद्य विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

इन जिलों में प्रभावित हुआ गेहूं

इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, सिवनी, रीवा, टीकमगढ़, मंडला, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, भिंड, शाजापुर, आगर मालवा, सागर, छिंदवाड़ा, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा।

इनका कहना है

मुख्यमंत्री की पहल पर पिछले साल भी केंद्र सरकार ने चमकविहीन गेहूं खरीदने की अनुमति दी थी। इसी वजह से मप्र गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बना सका था। इस बार भी 24 जिले बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित रहे हैं। यदि केंद्र सरकार अनुमति नहीं देती है तो किसानों को औने-पौने दाम पर गेहूं बेचना होगा।

अभिजीत अग्रवाल, प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

सप्ताह में पांच दिन होगी खरीदी दो दिन होगा पैसों का हिसाब

इधर, गुरुवार से गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन बहुत कम संख्या में किसान खरीदी केंद्र पहुंचे। कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए किसी भी केंद्र पर 20 से ज्यादा किसानों की एक समय में मौजूदगी पर रोक लगाई गई है। वहीं, भुगतान में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए खरीद सप्ताह में पांच दिन होगी। दो दिन हिसाब-किताब होगा और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। गर्मी को देखते हुए उपार्जन केंद्रों में किसानों के बैठने के लिए छांव और पानी का इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए, यह जरूर सुनिश्चित कर लें। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 24 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। किसान जल्दबाजी न करें। एक-एक किसान से गेहूं खरीदा जाएगा। किसानों को फसल बेचने से लेकर भुगतान तक में कोई समस्या न हो, इसका इंतजाम सरकार ने किया। इसके बाद भी यदि कोई समस्या आती है तो उस संबंध में किसान टोल फ्री सीएम हेल्प लाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जिलेवार गेहूं खरीदी का लक्ष्य

मंदसौर: जिले में 2.25 लाख टन उपज की खरीदी होगी। 146 गोदामों में भंडारण होगा। पिछले साल जिले में गेहूं की 2.80 लाख टन खरीदी हुई थी। गोदामों में एक लाख मीट्रिक टन गेहूं भरा है।

खंडवा: जिले में 2 लाख 30 हजार मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। भंडारण के लिए 65 गोदाम हैं। इनकी क्षमता साढ़े तीन लाख टन गेहूं की है।

आलीराजपुर: जिले में 3200 टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। यहां भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था है।

खरगोन: जिले में दो लाख टन खरीदी का लक्ष्य है। 61 गोदामों में 1 लाख 63 हजार टन गेहूं भंडारण की क्षमता है, वहीं करीब 28 हजार टन गेहूं को जरूरत पड़ने पर ओपन कैप में रखा जाएगा।

शाजापुर: जिले में चार लाख 80 हजार उपज की खरीदी की संभावना है। चार लाख 30 हजार टन उपज गोदामों में रखेंगे। शेष सायलो सेंटर में भंडारण होगा।

धार: जिले में गेहूं की खरीदी का लक्ष्य तीन लाख 75 हजार टन है। जिले के 98 गोदामों की क्षमता 3 लाख 66 हजार है।

सही उत्पादन नहीं होने से किसानों को हुआ नुकसान

पीला मोजेक रोग से पपीते की फसल बर्बाद

संवाददाता, सागर

परंपरागत फसल लेने वाले रहली के करीब आधा दर्जन किसानों ने इस बार नवाचार करते हुए गेहूं, चने की जगह पपीता की खेती की थी। शुरुआत में तो खेती ठीक रही, लेकिन इसके बाद वह पीला मोजेक रोग की चपेट में आ गई। इससे पत्ते पीला होने लगे। फल में भी रोग लग गया। इससे अपेक्षा के मुताबिक उत्पादन नहीं हो रहा है। किसानों का कहना है कि पपीता की लागत निकलना ही मुश्किल लग रहा है। किसानों ने कहा कि खेती में उन्हें घाटा जरूर हुआ है, लेकिन उन्हें नवाचार करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे आगे फायदा होगा।

प्रति एकड़ 5 लाख की थी उम्मीद

रहली ब्लॉक के कंदला पंचायत के कुमेरिया गांव के किसान जयराम कुर्मी ने बताया कि उन्होंने एक एकड़ में पपीता के एक हजार पौधे लगाए थे। पौधे 30 हजार रुपए में आए थे। 30 हजार की रसायनिक उर्वरक का छिड़काव किया। वहीं 30 हजार में मल्चिंग सहित मजूदरी का खर्च आया है। 30 प्रतिशत पौधों में तो अच्छी फसल आई, लेकिन 70 प्रतिशत पौधे ऐसे रहे, जिन्में प्रति पौधा 40 किग्रा की उम्मीद थी, लेकिन 8 से 10 किग्रा ही उपज हुई है।

निगरानी में करेंगे काम

चनौआ के किसान रमाकांत पटेल, शुभम पटेल के अनुसार हर साल कभी अधिक बारिश तो कभी सूखा व अन्य कारणों से सोयाबीन, गेहूं-चने की फसल प्रभावित हो जाती है। लगातार ऐसा होने से खेती के प्रति मन में निराशा आ गई थी। इसके बाद फलों की खेती पर विचार किया और पपीते की खेती शुरू की। इसमें पीला मोजेक रोग लगने से उपज प्रभावित हुई है। यह पहला साल था। इसलिए उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं हुआ। यदि संभव हुआ तो पूरी ट्रेनिंग व विशेषज्ञों की निगरानी में फिर काम किया जाएगा। इससे फायदा संभव है।

इनका कहना है

पपीता सबसे कम समय में फल देने वाला वृक्ष है। किसानों ने उत्साह के साथ इसकी खेती की थी। पहली साल अपेक्षाकृत मुनाफा नहीं हुआ। इस पर आगे भी काम किया जाएगा। यह नवाचार था। अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं आए। आगे सफलता की उम्मीद है।

सोमनाथ राय, जिला अधिकारी, उद्यानिकी विभाग, सागर

हमें पपीता की फसल से प्रति एकड़ पांच लाख रुपए के फायदे की उम्मीद थी, लेकिन लागत ही निकल आए यह बहुत मुश्किल लग रहा है। नवाचार के तौर पर की गई पपीता की खेती से घाटा जरूर हुआ, लेकिन हमें सीखना के लिए भी बहुत कुछ मिला है। अगली बार जरूर सफलता मिलेगा।

जयराम कुर्मी, किसान, रहली ब्लॉक

रानीघाटी में दो तालाब बनाने से 2000 गायों को मिला पानी

गौमुख से बहने वाला झरना भी दशकों बाद हो गया चालू

संवाददाता, ग्वालियर

रानीघाटी की पथरीले पटार पर कोरोनाकाल के दौरान जिला पंचायत के तात्कालीन सीईओ ने मनरेगा के माध्यम से दो तालाबों का निर्माण कराया था। इन तालाबों के कारण यहां पर रहने वाली 2000 गायों को जीवनदान मिला है। इसके साथ ही यहां पर गौमुख से हमेशा बहने वाला झरना जो दो दशकों से बंद पड़ा था, वह भी चालू हो गया है। राजा नल की जन्मस्थली रानीघाटी पर भगवान रामजानकी का मंदिर है। इसके आसपास 30 वर्ग किमी में जंगल है। जिसके चलते यहां पर पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की व्यवस्था है। मंदिर के पास जिला पंचायत ने गौशाला का निर्माण करा दिया। गौशाला की देखरेख श्रीकृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के संत करते हैं, लेकिन यहां पर पानी की काफी समस्या थी। गर्मियों में पशुओं और गायों के लिए पानी नहीं होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके चलते श्रीकृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के संतों ने यहां पर तालाबों का निर्माण प्रारंभ कराया। तालाबों का निर्माण कार्य का पता चलने पर तात्कालीन जिला पंचायत सीईओ शिवम वर्मा ने दो तालाबों का निर्माण मनरेगा के माध्यम से कराया। इसके चलते यहां पर रहने वाली 2000 गायों को 8 माह तक पानी की व्यवस्था हो गई। इसके साथ ही जंगल में रहने वाले हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू आदि के लिए भी पानी की व्यवस्था हो गई।

पूरे क्षेत्र में सफेद पत्थर: रानीघाटी का क्षेत्र सोनचिरैया अभ्यारण के पास ही लगा है। यहां का पूरा क्षेत्र सफेद पत्थर का है, जिसके कारण यहां पर तालाब आदि के निर्माण में काफी परेशानी आती है।

इनका कहना है

रानीघाटी गौशाला को दो तालाबों के निर्माण से काफी मदद मिली है। इससे गायों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो गई। साथ ही चरवाहे भी अपनी गायों एवं बकरियों को यहां पर पानी पिलाने के लिए लाने लगे हैं। रात के समय जंगली जानवर भी काफी मात्रा में आते हैं।

■ **ऋषभानंद महाराज,** श्रीकृष्णादेशी गौरक्षाशाला

» अंचल के किसानों ने बिचौलियों को कर दिया दरकिनार

» अब तक 2 लाख 10 हजार क्विंटल से ज्यादा सरसो बिकी

» व्यापारियों ने एक अरब आठ करोड़ रुपए का किया भुगतान

चंबल में सरसो के मिल रहे रिकॉर्ड तोड़ भाव

अवधेश डंडोतिया, मुरैना

सरसों के भाव इस साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सरसों पर आई यह महंगाई न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि कृषि मंडियों के लिए भी लाभकारी साबित हुई है। किसानों ने बिचौलियों के चक्र को तोड़ते हुए समर्थन मूल्य से 500 से 600 रुपए अधिक में सरसों बेची है। बढ़ी आवक और कम समर्थन मूल्य को देखते हुए मंडी में व्यापारियों ने किसानों को कम दाम देने का कई बार प्रयास किया, परंतु इस समय किसानों के समर्थन में सरकार और स्थानीय प्रशासन के रुख के कारण वे हावी नहीं हो पाए। सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य पर 4650 रुपए क्विंटल तय किया है, जबकि बाजार में सरसों के दाम 5000 से लेकर 5200 तक है। यही कारण है कि समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीदी शुरू होने से पहले ही मुरैना जिले में एक लाख 70 हजार 500 क्विंटल सरसों को किसान कृषि मंडी में व्यापारियों को बेच चुके।

मंडी को मिला 1.20 करोड़ का टैक्स: कोरोना काल में मुरैना सहित कई मंडियों की हालत ऐसी थी कि कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं बांट पा रहे थे। वहीं मार्च में मुरैना मंडी में सरसों की रिकॉर्ड खरीदी-बिक्री से एक करोड़ 20 लाख रुपए का टैक्स मिला है। मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी को उपज खरीदी का 1.5 प्रतिशत मंडी टैक्स के मंडी देना होता है। यही मंडी की कमाई है।

इसलिए महंगी हो रही सरसों

अभी सरसों की पैदावार का सीजन है। इस सीजन में सरसों के दाम घटते थे, लेकिन पहली बार सरसों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दरअसल, देश में तेल की मांग की पूर्ति के लिए विदेशों से राइसब्रान, पाम आइल आदि का आयात होता है। सरकार ने पिछले महीनों में तेल के आयात पर टैक्स दरों को बहुत अधिक कर दिया है। इस कारण विदेशी तेल का आना लगभग बंद सा हो गया है और इसके बाद से देश में सरसों के तेल की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी पूर्ति को पूरा करने का असर सरसों व उसके तेल के दामों पर पड़ रहा है।

सरसों के दाम अच्छे होने से किसान समर्थन मूल्य की जगह व्यापारियों को सरसों बेचना पसंद कर रहे हैं। यह कृषि मंडी के लिए भी वरदान साबित हुआ है। मार्च में मुरैना मंडी ने 1.20 करोड़ का टैक्स कमाया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अगर दाम यही रहे तो बाकी किसान भी समर्थन मूल्य की जगह मंडी में ही सरसों बेचेंगे। कई बैंक व्यापारियों को पैसा ही नहीं दे पा रहे हैं।

-शिवप्रताप सिंह सिकरवार, मंडी सचिव, मुरैना

समर्थन मूल्य खरीदी की तुलना में मंडी में सरसों के दाम 500 से 600 रुपए क्विंटल ज्यादा है। मंडी में नगद पैसा भी मिल जाता है। इसीलिए हर किसान अपनी सरसों मंडी में ला रहा है। व्यापारियों के पास जितनी रकम थी और जब तक बैंकों ने मांग अनुसार भुगतान किया तब तक सही खरीदी चली। अब बैंकों से पैसे ही नहीं मिल रहे, ऐसे में व्यापारी कैसे खरीद करें।

सुधीर गोयल, संभाग प्रभारी, व्यापार महासंघ

बैंकों में हुआ नकदी का संकट

कृषि उपज मंडियों में हो रही सरसों की बंपर खरीदी से मुरैना जिले की कईयों बैंकों में नकदी का संकट आ गया है। हालत यह है कि जो व्यापारी बैंक में 50 लाख निकालने जा रहा हैं उसे 5 से 10 लाख रुपए ही मिल पा रहे हैं। इससे जिलेभर की मंडियों में सरसों की खरीद पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों को बैंकों से पैसे नहीं मिल पा रहे, इस कारण कैलारस की कृषि मंडी में तो व्यापारियों ने पांच दिन तक खरीद नहीं करने का ऐलान कर रखा है। अब तक 2 लाख 10 हजार क्विंटल से ज्यादा सरसों बेच चुके हैं। व्यापारियों ने किसानों को अब तक एक अरब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भुगतान कर दी है।

सागर में होली पर गौकाष्ठ के उपयोग से बचीं लकड़ियां

» अगले साल गोबर में मिलाएंगे चंदन का पाउडर

» अच्छी मांग के चलते अधिकारियों ने लिया निर्णय

संवाददाता, सागर

होलिका पर लकड़ी बचाने की मुहिम के रूप में गौकाष्ठ की बिक्री किए जाने की पहल पहले साल ही सफल होती दिखी। परिणाम अच्छे आने पर प्रशासन ने आगामी साल से इसमें और सुधार किए जाने की रणनीति बनाई है। इस बार पहली बार गौकाष्ठ बिक्री के लिए सागर में विक्रय केंद्र बनाया गया, जहां पांच हजार रुपए से अधिक का गौकाष्ठ बिका। गौकाष्ठ के लिए आम लोगों के अलावा अधिकारियों ने भी रुचि दिखाई। उन्होंने अपने क्षेत्र में जलने वाली होलिका के लिए गौकाष्ठ लिया। वहीं अब प्रशासन ने तय किया है कि अगले साल होलिका के लिए गौकाष्ठ तैयार करते समय उसमें चंदन का पाउडर मिलवाया जाएगा, जिससे होलिका दहन के बाद चंदन की खुशबू से पूरा क्षेत्र महक उठे।

सप्लाई का बनाया प्रस्ताव

गौरतलब है कि बरायठा गौशाला में गोबर से समूह की महिलाएं गौकाष्ठ व गौमूत्र से विभिन्न उत्पाद बना रही हैं। इसकी सप्लाई नगर पालिकाओं व नगर पंचायत क्षेत्र में हो सके। इसलिए वहां के अधिकारियों से चर्चा की है। खासकर श्मशान घाटों में गौकाष्ठ सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव बनाया गया है।

इनका कहना है

अगली बार से होलिका दहन के लिए अलग से गौकाष्ठ तैयार कराएंगे। उस गौकाष्ठ में चंदन का पाउडर मिलवाया जाएगा, जिससे उसके जलते ही चंदन की खुशबू महक उठे। यह पहला साल था। परिणाम अच्छे आए हैं। सुधार से और भी परिणाम बेहतर आने की उम्मीद है।

डॉ. इच्छित गढ़पाले, सीईओ, जिला पंचायत, सागर

हमारे क्षेत्र बरायठा गांव के रामराजा महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही शहर में भी गोकाष्ठ व कंडे उपलब्ध कराए हैं। गौकाष्ठ के होलिका में उपयोग से लकड़ी और वनों की बर्बादी को रोका जा सकता है। यह पहला साल था। इसमें सफलता मिली है। आगे और बेहतर ढंग से कार्य किया जाएगा।

अंबिका ठाकुर, ब्लॉक समन्वय, आजीविका मिशन शाहगढ़

» इंदौर आईआईटी ने विकसित की तकनीक

» 20 हजार फ्लाई ऐश ब्रिक निर्माण का अनुमान

कम लागत में पत्थर के चूरे से बनी रंगीन ईंटें

संवाददाता, इंदौर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर ने कम लागत में पत्थर के चूरे से रंगीन ईंटें बनाने की नई तकनीक विकसित की है। संस्थान के ग्रामीण विकास एवं तकनीकी केंद्र ने सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिकी अभियांत्रिकी एवं भौतिकी विभाग के साथ मिलकर ब्रिक प्रयोगशाला में इन विशिष्ट ईंटों को विकसित किया है। संस्थान के प्राध्यापक, डॉ. संदीप चौधरी, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. अंकुर मिगलानी एवं शोध विधार्थी विवेक गुप्ता, देवेश कुमार ने सजावटी पत्थर को तैयार करने वाली इंडस्ट्री से निकलने वाले व्यर्थ पड़े लाखों टन रंगीन पत्थर के चूरे से मजबूत रंगीन ईंटों का निर्माण कर दिखाया है। इन्हें खास तौर पर ग्रामीण परिवेश में उपयोग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। प्रारंभिक स्तर पर इस शोध कार्य में पश्चिमी भारत के चार प्रमुख स्टोन्स धौलपुर, जैसलमेर, कोटा एवं मकराना को उपयोग में लिया है जिन्हें आसानी से अन्य स्टोन वेस्ट के साथ भी दोहराया जा सकता है।

वेस्ट मटेरियल का उपयोग

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स जर्नल में प्रकाशित हुए इस शोध कार्य में आईआईटी इंदौर के विद्यार्थियों ने रंगीन पत्थर के चूरे में स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाले एक अन्य वेस्ट मटेरियल

को मिलाकर केमिकल के जरिये एक ऐसे मजबूत रंगीन कम्पोजिट में तब्दील किया है जिसे ईंटें बनाने के काम में लिया जा सकता है।

प्लास्टर-पेंट की जरुरत नहीं

केमिकल के कारण आने वाली लागत को कम करने के लिए उन्होंने इस मजबूत पदार्थ को ईंटों में सीमित मोटाई तक उपयोग में लिया है और दो लेयर वाली ऐसी विशिष्ट ईंटें बनाई है जिनका उपयोग करने पर प्लास्टर और पेंट करने की जरुरत नहीं होगी। ऐसी दो लेयर वाली ईंटों में ऊपर की लेयर में मजबूत रंगीन कंपोजिट का प्रयोग किया हैं एवं नीचे की लेयर में सामान्य फ्लाई ऐश ईंटों का मसाला उपयोग में लिया गया है।

मजबूता और टिकाऊ

फ्लाई ऐश की ईंटो को कृत्रिम रंगों से आसानी से रंगीन बनाया जा सकता था लेकिन फिर ईंटो की कम लागत में तैयार करना मुश्किल हो पाता। इसलिए शोधार्थियों ने वेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया और रंगीन पत्थर का चूरा जो कि मजबूत और टिकाऊ होते हैं उनका उपयोग करके रंगीन ईंटों को विकसित किया।

इनका कहना है

संस्थान में प्री-मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों एवं वेस्ट मटेरियल के लाभदायक उपयोग के क्षेत्र में पिछले चार सालों से गहन शोध कार्य चल रहा है। शोधार्थियों को पता चला कि ग्रामीण परिवेश में आज भी आग में तपकर बनी लाल रंग की ईंटों को शुभ रंग की होने के कारण फ्लाई ऐश से पर्यावरण के अनुकूल बनी ग्रे रंग की ईंटों के बजाय प्राथमिकता दी जा रही है। आग में तपकर बनी लाल ईंटें वातावरण को प्रदूषित करती हैं। देश के बहुत से राज्यों में इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर रोक भी लगाई गयी है।

डॉ. संदीप चौधरी, प्राध्यापक, आईआईटी, इंदौर

भोपाल में प्रतिदिन 400 टन कचरे से बनाया जाएगा ईंधन

- एनटीपीसी कंपनी आदमपुर छावनी में स्थापित करेगी प्लांट
- 15 एकड़ जमीन के समतलीकरण का काम शुरू किया गया
- खासियतः ईंधन का उपयोग कोयले की तरह किया जाएगा
- फायदाः नगर निगम को होगी बड़ी बचत होगी
- उपलब्धिः शहर को कचरे के ढेर से भी मुक्ति मिलेगी
- कचरे से ईंधन बनाने वाले प्लांट की लागत 80 करोड़ रुपए

संवाददाता, भोपाल

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा भोपाल शहर से निकलने वाले कचरे में से हर दिन चार सौ टन कचरे से ईंधन बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस ईंधन का उपयोग कोयले की तरह किया जा सकेगा। इससे न केवल नगर निगम को बड़ी राशि की बचत होगी बल्कि शहर को कचरे के ढेर से भी मुक्ति मिल सकेगी। कचरे से ईंधन बनाने वाले प्लांट की लागत 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा आदमपुर छावनी में स्थापित किया जा रहा है। करीब डेढ़ साल से जारी मशक्कत के बाद अब इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 15 एकड़ जमीन के समतलीकरण का काम शुरू कर दिया गया है।

कोयले की तरह होगा उपयोग

अभी दावा किया जा रहा है कि एनटीपीसी प्लांट द्वारा एक तय तापमान पर कचरे से ईंधन का बंडल बनाया जाएगा, जिसका उपयोग कोयले की तरह किया जा सकेगा। इसमें भी खास बात यह है कि नगर निगम को एक भी पैस खर्च नहीं होगा, बल्कि कचरे की प्रोसेसिंग में हर साल होने वाले करीब पांच करोड़ की राशि की भी बचत हो सकेगी। माना जा रहा है कि यह प्लांट इसी साल बनने के बाद काम करना शुरू कर देगा।

शहर में कचरे की स्थिति

800 टन कचरा प्रतिदिन	440 टन कचरा कचरा
360 टन कचरा गीला	433 गाड़ियां संग्रहण में लगीं

छह एकड़ में होगा बॉयो सीएनजी का भी प्लांट

दरअसल, भोपाल के प्रवेश मार्ग भानपुर के पास कचरे का पहाड़ खत्म करने के बाद अब निगम अधिकारियों का पूरा फोकस आदमपुर छावनी पर है। यहां पर शहर का अधिकांश कचरा डंप किया जाता है। फिलहाल भोपाल नगर निगम द्वारा यहां पर हर दिन 20 टन कचरा ही साफ किया जा रहा है। यह शहर से निकलने वाले कचरे की तुलना में बहुत कम है। यही वजह है कि निगम द्वारा लंबे समय से सूखे और गीले कचरे से चारकोल व सीएनजी निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे थे। एनटीपीसी द्वारा अब यहां पर छह एकड़ में बॉयो सीएनजी प्लांट और 15 एकड़ में चारकोल प्लांट स्थापित किए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है।

बिजली प्लांट में होगा उपयोग

कचरे से बनाए जाने वाले ईंधन का उपयोग बिजली प्लांटों में किया जाएगा। इसके लिए एमओयू होने के बाद अब अंतिम रूप से अनुबंध करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए एनटीपीसी द्वारा प्लांट की स्थापना में किए जा रहे बदलावों को पूरा होने का इंतजार है। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही फाइनल एग्रीमेंट होगा, उसके तत्काल बाद प्लांट स्थापना का काम शुरू कर दिया जाएगा।

गीले कचरे से बनेगी सीएनजी, दौड़ेंगी बस

गौरतलब है कि हाल ही में आदमपुर छावनी स्थित लैंडफिल साइट पर क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने बायो सीएनजी प्लांट का भूमिपूजन किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट में प्रतिदिन दो सौ टन गीले कचरे को निष्पादित कर सीएनजी गैस बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट में नगर निगम का एक रुपए भी खर्च नहीं होगा साथ ही नगर निगम को हर साल 61 लाख की रॉयल्टी भी मिलेगी। प्रोजेक्ट भी 15 माह के अंदर पूरा किया जाएगा।

दो प्रोजेक्ट पर होगा काम

तीन सौ टन सूखे कचरे की री-साइकलिंग के लिए ड्राय वेस्ट मेटेरियल रिकवरी प्रोजेक्ट पर अहमदाबाद की नेप्रा कंपनी काम करेगी। शर्तों के मुताबिक कंपनी से नगर निगम को कचरे के बदले 38 लाख रुपए सालाना आय भी होगी। इसमें कई प्रकार की मशीनों का बड़ा सेटअप होगा। दो से तीन माह में प्लांट में मशीन व सेटअप संबंधित पूरा हो सकता है।

प्रोजेक्ट-कचरे से ईंधन प्लांट

कचरे का निष्पादन- 400 टन से अधिक कचरा प्रतिदिनः दोनों प्रोजेक्ट के बाद प्रतिदिन 400 टन कचरे के निष्पादन के लिए एनटीपीसी का कचरे के रूप में ईंधन बनाने का प्रोजेक्ट लगाया जाना है। प्लांट में कचरे को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए काम होगा। पहले कचरे की आर्द्रता को खत्म किया जाएगा। फिर कंप्रेसिंग कर निश्चित ताप में कचरे को ईंधन के लिए बंडल का आकार दिया जाएगा।

एक नजर में प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट का नाम- बायो सीएनजी प्लांट
कंपनी का नाम- नासिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी
लागत- 30 करोड़ रुपए
डेडलाइन- 15 महीने
प्लांट का क्षेत्रफल- 6 एकड़
कितना कचरा- 200 टन गीला कचरा
नगर निगम का खर्च- एक रुपए नहीं
बचने वाला निगम का खर्च- 2.43 करोड़
यूनिडो से मिलने वाला अनुदान- 10.50 करोड़
गैस का उपयोग- बीसीएलएल की बसों के संचालन में
ननि को कितने में मिलेगी- बाजार से पांच रुपए कम में
कितना कंपोस्ट बनाया जाएगा- 20 टन
कितने वर्षों का अनुबंध- 20 वर्ष

इनका कहना है

यदि प्रोजेक्ट में देरी हुई या लोगों को दिक्कत हुई तो संबंधित अफसरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्लांट में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने पर फोकस रहेगा।

रामेश्वर शर्मा, विधायक

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिंण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)